दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 12.12.2023
उद्घोषित: 22.12.2023

<u>आप.वि.वा. 9100/2023 और आप.वि.आ. 33976/2023</u>

विनोद कुमार और अन्य .....याचिकाकर्तागण

द्वारा: श्री तनवीर अहमद मीर, श्री कार्तिक वेणु, श्री वैभव सूरी और सुश्री एरियाना अहलूवालिया, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य (रा.रे.क्षे. दिल्ली) और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री मनोज पंत, राज्य के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय की अनुक्रमणिका</u>

वास्तविक पृष्ठभूमि..... 3
आक्षेपित आदेश.....6
इस न्यायालय के समक्ष उठाये गए विषय..... 8
क्या आक्षेपित आदेश "न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021" के आदेश का उल्लंघन करता है?..... 11

क्या अभियोक्त्री को दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाही देने की अनुमति देने से अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन होगा? 16

क. कमजोर गवाहों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक मिसालें और निर्देश: इसकी शुरूआत कैसे हुई..... 17

ख. असुरक्षित गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखन: दिल्ली उच्च न्यायालय की योजना..... 26

ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की न्यायिक मिसालें..... 28

घ. दांडिक विचारण में अभियुक्त और पीड़ित के अधिकारों को संतुलित करते हुए प्रौद्योगिकी को अपनाना..... 38

ङ. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य अर्थात गवाह के आचरण की रिकॉर्डिंग..... 40

च. क्या 'विकसित देश से आने वाली शिक्षित महिला' को 'कमजोर गवाह' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है?..... 41

निष्कर्ष..... 43

<u>न्या. स्वर्ण कांता शर्मा</u>

1. वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.सं.प्र.') की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एस.एफ.टी.सी.) - नई दिल्ली, पटियाला हाउस जिला न्यायालय, नई दिल्ली, द्वारा सत्र मामला

सं. 379/2019 में दिनांक 09.12.2023 को पारित आदेश को अपास्त करने की मांग करते हुए, दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता विनोद कुमार और राजेश कुमार हैं, जिसे एक अन्य अभियुक्त अनिल कुमार, के साथ सामूहिक बलात्कार के कथित मामले में विचारण का सामना करना पड़ रहा है, इस न्यायालय के विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा, निर्देश देने की मांग करता है, कि अभियोक्त्री से परीक्षा और प्रतिपरीक्षा के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए दबाब डालना है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

3. इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर करने के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं का क्रम यह है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला कांगड़ा, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक अभियोक्त्री 'एक्स' उम्र लगभग 23 वर्ष द्वारा शिकायत की गई थी, उसने बताई कि वह भारत इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 3, शिकागो, अमेरिका से 15.05.2019 को शाम 6:40 बजे पहुँची थी। शिकायत में आगे कहा गया कि उसे अगले दिन यानी 16.05.2019 को सुबह 6:30 बजे दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ्लाइट पकड़नी थी और इसलिए वह रात भर एयरपोर्ट पर ही सोई थीं। हालाँकि, अगली सुबह, दुर्भाग्य से उसकी धर्मशाला के लिए फ्लाइट छुट गई थी। संबंधित एयरलाइंस से अपना सामान प्राप्त करने के बाद, अभियोक्त्री हवाई अड्डे से बाहर निकली, जहाँ उसे दो व्यक्ति अर्थात 'लाल सिंह

और 'कुमार' *(जैसा कि शिकायत में उल्लेख किया गया है)* मिला, जिन्होंने खुद को टैक्सी चालक के रूप में प्रस्तुत किया था और धर्मशाला के लिए बस टिकट प्राप्त करने में उसकी मदद करने की पेशकश की थी। अभियोक्त्री तदनुसार उसके वाहन में बैठी, और लगभग 5-10 मिनट के बाद, उन्होंने एक बाजार के पास कार रोकी और उसके लिए बस का टिकट लाया, जिसके लिए उसने उन्हें रु.10,000/- और 20 अमरीकी डॉलर का भुगतान किया था। इसके बाद, इन दोनों व्यक्तियों ने अभियोक्त्री को आश्वस्त किया कि चूँकि बस कश्मीरी गेट से शाम के 6:50 बजे रवाना होने वाली है और अभी सुबह के 10:30 ही बजे हैं, इसलिए उसे होटल में रुकना चाहिए। इसके बाद वे उसे नई दिल्ली के वसंत कुंज के एक होटल में ले गए। आरोप है कि ये अभियुक्त अभियोक्त्री के कमरे में घुसे, और फिर उसके साथ बलात्कार किया था। इनमें से एक अभियुक्त ने अभियोक्त्री द्वारा पहनी हुई अंगूठी भी ले ली थी। इसके बाद, शाम को, उन्होंने अभियोक्त्री को कश्मीरी गेट छोड़ने की पेशकश की, और रास्ते में, अभियोक्त्री ने एल.एच.ए. पूर्त न्यास मैकलियोडगंज, हिमाचल प्रदेश से संपर्क किया था उस व्यक्ति से बात की कि अभियुक्त का नाम 'कुमार' है। इसके बाद, अभियुक्त ने अभियोक्त्री को पटियाला हाउस न्यायालय के पास छोड़ दिया और वहाँ से, वह कश्मीरी गेट तक टैक्सी में यात्रा की थी। बस में चढ़ने पर उसे पता चला कि अभियुक्त द्वारा उसे दी गई गया बस टिकट नकली था। यह कहा गया कि उसके बाद, उसे धर्मशाला के लिए एक साधारण बस में चढ़ना पड़ा, और वह 17.05.2019 की सुबह अपने गंतव्य पहुँची थी। 20.05.2019 को, अभियोक्त्री

ने इस घटना के बारे में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को बताया और उनके निर्देश पर, उसने एस.एस.पी. कार्यालय, धर्मशाला से संपर्क किया था और वर्तमान शिकायत दर्ज कराई थी।

4. चूँकि अपराध कथित रूप से दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में किया गया था, मामला दिल्ली को भेज दिया गया था, और वर्तमान प्राथमिकी सं. 0119/2019 वसंत कुंज उत्तर, पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376घ/379 के तहत (भा.दं.सं.) दर्ज की गई थी। जाँच के दौरान, अभियोक्त्री का सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सकीय रूप से जाँच की गई थी जहाँ उसके साथ तीन व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न बताया गया था।

5. जैसा कि याचिका में बताया गया है, याचिकाकर्ता यानी विनोद कुमार और राजेश कुमार और तीसरा अभियुक्त अनिल कुमार, सभी को वर्तमान मामले में 21.05.2019 को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद जाँच पूरी होने पर, दिनांक 16.08.2019 को भा.दं.सं. की धारा 376घ/377/379/411के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। वर्तमान मामले का विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 19.08.2019 को संज्ञान लिया गया था और मामला 21.08.2019 को विद्वान सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था। सबसे पहले अभियोजन द्वारा 01.09.2021 को पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद, दिनांक 22.03.2022 के आदेश के द्वारा, विद्वान विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 376घ/379/411 के तहत तीन अभियुक्तों के

खिलाफ आरोप तय किए थे। चूँकि दिनांक 04.07.2022 के आदेश के द्वारा अभियोक्त्री का पता नहीं चल पा रहा था, विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित डी.सी.पी. को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अभियोक्त्री पूछताछ करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया और रिपोर्ट मांगी। इसके बाद, एक रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें उल्लेख किया गया था कि अभियोक्त्री संबंधित आई.ओ. के ई-मेल और संदेशों या विदेश मंत्रालय द्वारा उसे दिए गए समन का जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने विदेश मंत्रालय द्वारा नए समन जारी करवाए और एक बार फिर निर्देश दिया कि संबंधित आई.ओ. या एस.एच.ओ. अभियोक्त्री से या तो शारीरिक रूप से या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संपर्क करें। 26.11.2022 को, विद्वान विचारण न्यायालय ने अवलोकित किया कि अभियोक्त्री को खुद की जाँच करने का पर्याप्त अवसर पहले से दिया जा चूका है और उसके बाद, उसे एक अंतिम मौका दिया गया। आखिरकार, 13.12.2022 को, अभियोक्त्री का स्वयं से पूछताछ करने के अधिकार को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बंद कर दिया गया था क्योंकि वह अदालत में पेश होने में विफल रही थी। 17.02.2023 को, अभियोजन साक्ष्य को बंद कर दिया और 02.03.2023 को, सभी अभियुक्तों का बयान द.प्र.सं. की धारा 311 के तहत दर्ज किया गया था इसके बाद, 15.03.2023 को अंतिम दलीलें सुनी गईं। यह कहा गया है कि 27.03.2023 को, याचिकाकर्ताओं को वर्तमान मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दे दी गई। दिनांक 20.04.2023 के आदेश के अनुसार,

विद्वान विचारण न्यायालय ने एक बार फिर संबंधित आई.ओ. और एस.एच.ओ. को निर्देश दिया था आखिरी बार अभियोक्त्री से संपर्क करे।

6. अंत में, 11.09.2023 को, अभियोक्त्री विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शामिल हुई और कहा कि वह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा गवाही दे सकती है क्योंकि वह शिकागो, इलिनोइस, अमेरिका की निवासी है।

<u>आक्षेपित आदेश</u>

7. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 29.11.2023 को एक आवेदन दायर किया था जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय से वर्तमान मामले में अभियोक्त्री 'एक्स' से पूछताछ करने और प्रतिपरीक्षा करने के लिए उसे शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए उचित निर्देश की मांग की गई थी। हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.12.2023 के आक्षेपित आदेश के द्वारा याचिकाकर्ताओं की अभियोक्त्री की शारीरिक रूप से उपस्थित होने की मांग करने वाली आवेदन को खारिज कर दिया। आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> " ...इस नियम पर भरोसा करते हुए, आवेदक ने तर्क दिया कि गवाह के साक्ष्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिकॉर्डिंग के लिए अभियुक्त की सहमति की आवश्यकता होती है। इस पहलू पर, ध्यान देना उचित है कि दिनांक 02.03.2022 के आदेश द्वारा, अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए। 04.07.2022 को, अदालत ने संबंधित डी.सी.पी. को निर्देश दिया

कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री से पूछताछ करने की संभावना का पता लगाए, यदि वह शारीरिक रूप से अदालत में आने की स्थिति में नहीं है और संबंधित डी.सी.पी. से रिपोर्ट माँगा गया।

इसके अलावा, दिनांक 11.07.2022 के आदेश के अनुसार, अदालत ने अभियोक्त्री को समन देने का निर्देश दिया और उसे शारीरिक रूप से उपस्थित होने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपनी गवाही दर्ज कराने का अवसर दिया। अभियोक्त्री को विदेश मंत्रालय के द्वारा समन दिया गया और अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश और निर्देश पारित करने में कठिनाई महसूस की है। इसी तरह के निर्देश इस अदालत द्वारा 20.04.2023 को पारित किए गए थे। आवेदक/अभियुक्त को अच्छी तरह से पता था कि अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। बचाव पक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य दर्ज करने के अदालत के आदेश को चुनौती नहीं देने का विकल्प चुना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य दर्ज करने के अंतिम निर्देश 11.09.2023 को पारित किया गया था। अदालत पिछले एक वर्ष से अधिक समय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दे रही है। अभियुक्तों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के अदालत के निर्देशों पर कभी आपत्ति नहीं जताई है और यह दर्शाता है कि अभियुक्तों ने इस तरीके से साक्ष्य दर्ज करने के लिए निहित सहमति दी है।

इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री की गवाही दर्ज करने के अदालत के आदेश को बचाव पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। अब विधिक प्रश्न यह उठता है कि क्या इस अदालत के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दर्ज करने के निर्देश देने वाले अपने आदेश को वापस लेने का अधिकार है। आवेदन में अदालत से उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया था कि अभियोक्त्री को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दर्ज कराने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

यह विधि की सुस्थापित प्रतिपादना है कि दंड न्यायालय के पास अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है। दंड विधि में, पुनर्विचार का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, अभियोक्त्री को अपने साक्ष्य दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर करने की आड़ में यह आवेदन इस अदालत द्वारा दिनांक 04.07.2022, 11.07.2022, 20.04.2023 और 11.09.2023 को पारित आदेश की पुनर्विचार की मांग कर रहा है और इसलिए, यह पोषणीय नहीं है। पोषणीयता के अलावा, मैं इस अवसर पर यह अवलोकन किया कि शिकायतकर्ता/अभियोक्ता जघन्य अपराध सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई है और वह अमेरिका की निवासी है। यह अभियोक्त्री/पीड़िता को उत्पीड़ित करना होगा कि उसे इस मामले में विचारण के उद्देश्य से भारत आने के लिए जोर दिया जाय या मजबूर किया जाय। इसके अलावा, यदि अभियोक्त्री को अपने साक्ष्य दर्ज करने के लिए भारत आने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह राज्य के खजाने पर भारी बोझ होगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यदि अभियोक्त्री को साक्ष्य दर्ज करने के लिए भारत आने के लिए कहा गया तो वह उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुनेगी। इसके अलावा, तकनीकी प्रगति के इस युग में, निष्पक्ष विचारण के लिए अभियुक्त के अधिकारों से समझौता किए बिना अमेरिका में बैठे गवाह की गवाही रिकार्ड करना सुविधाजनक होगा। अदालत की सुविचारित राय है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री की गवाही दर्ज करने से निष्पक्ष विचारण में कोई बाधा नहीं होगी...”

8. उपरोक्त घटनाओं से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का रुख किया है।

<u>इस न्यायालय के समक्ष उठाये गए विषय</u>

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए निहित रूप से सहमति दी थी, दिनांक 04.07.2022, 11.07.2022, 20.04.2023 और 11.09.2023, के प्रक्रिया संबंधी पिछले आदेशों को चुनौती नहीं देने के आधार पर और न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा था कि ये सभी आदेश केवल अभियोजन पक्ष के परामर्श से और पूरी तरह से अभियुक्तों की सहमति या सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किए गए थे। यह भी कहा गया है कि इन आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि वे केवल अभियोक्त्री को शारीरिक रूप से उपस्थित होने या वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थित होने का अवसर देने के लिए पारित किए गए थे, और न्यायालय ने अंततः अभियोक्त्री को अपने साक्ष्य को दर्ज करने के उद्देश्य से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थित होने का निर्देश नहीं दिया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के नियम 5.3.11 में कहा गया है कि जहाँ भारत के बाहर स्थित किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले में गवाह से पूछताछ करनी है, अदालत वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऐसे गवाह से पूछताछ करने की अनुमति देने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकती है, हालाँकि, ऐसे मामलों में अभियुक्त की सहमति प्राप्त करनी होती है, जो वर्तमान मामले में प्राप्त नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि गवाह को शारीरिक रूप से बुलाना उत्पीड़न करने के बराबर होगा और राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ

पड़ेगा, हालाँकि, कथित अपराध की गंभीरता और ऐसे मामलों में अभियोक्त्री की गवाही के महत्व को देखते हुए, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्ता से पूछताछ न्याय के हित में नहीं होगी, और यही कारण है कि अभियोक्त्री द्वारा प्रतिपरीक्षा के पवित्र अधिकार को गलत तरीके से कम कर देगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त की ओर से प्रभावी प्रतिपरीक्षा, बिना किसी रुकावट के वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो सकता है, अभियुक्त का यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे न्यायालयों द्वारा संरक्षित किया जाना है। यह तर्क दिया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं को वर्तमान मामले में दोषी ठहराया जाता है, तो प्रश्नगत अपराध के लिए सजा 20 साल तक हो सकता है और इस प्रकार, विचारण न्यायालय का परिणामी कर्तव्य है अभियुक्त के अधिकारों को पीड़ित के अधिकार के साथ संतुलित करना है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायालयों के पास गवाहों की प्रतिक्रियाओं, लहज़े और आचरण को रिकॉर्ड करने की शक्ति है, जिस पर गवाह से प्रतिपरीक्षा के दौरान विचार किया जाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है। इन परिस्थितियों में, यह प्रार्थना की जाती है कि आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए और वर्तमान मामले में अभियोक्त्री को साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से और अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए।

10. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. ने याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना के अनुसार राहत देने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान मामला वर्ष 2019 में एक विदेशी नागरिक के यौन उत्पीड़न से संबंधित है जब वह भारत की यात्रा पर थी। यह कहा गया है कि इस न्यायालय द्वारा बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के साथ-साथ माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा कई अन्य निर्णयों में निर्देश दिए गए हैं और यौन उत्पीड़न मामले में किसी विदेशी नागरिक से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूछताछ करने की हमेशा अनुमति दी गई है। यह कहा गया है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग दांडिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह भी कहा गया है कि विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि पक्षकार और अदालत गवाह के आचरण का अवलोकन करने में सक्षम नहीं होंगे, को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि बयान की सत्यता पूरी तरह से गवाह के आचरण पर निर्भर नहीं करती है, जिसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और विद्वान न्यायाधीश द्वारा भी अन्यथा नोट किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यह न्यायालय द.प्र.सं. की धारा 284 के अनुसार विचारण कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से एक आदेश जारी करने का निर्देश दे सकता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान याचिका खारिज कर दिया जाय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाय।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष संबोधित तर्कों को सुना गया है, और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया है।

<u>क्या आक्षेपित आदेश "न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021" के आदेश का उल्लंघन करता है?</u>

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया पहला तर्क यह था कि विचारण न्यायलय द्वारा दिए गए निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के नियम 5.3.11 के खिलाफ हैं, और इस तरह के निर्देश पारित करने से पहले अदालत द्वारा अभियुक्त की कोई सहमति कभी भी नहीं ली गई थी।

13. यह न्यायालय ने "न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021" का अवलोकन किया है और प्रासंगिक नियम निम्नानुसार है:

> "5. तैयारी की व्यवस्थाएँ
>
> 5.1 न्यायालय में और दूरस्थ स्थान दोनों जगह एक समन्वयक होगा जहाँ से किसी भी अपेक्षित व्यक्ति की जांच या सुनवाई की जानी है। हालाँकि, दूरस्थ स्थान पर समन्वयक की आवश्यकता केवल तभी हो सकती है जब किसी गवाह या अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की जांच की जानी हो।
>
> 5.2 जिला न्यायपालिका के दायरे में आने वाले सिविल और दंड न्यायालयों में, उच्च न्यायालय या संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा नामित

व्यक्ति, नियम 5.3 में दिए गए अनुसार न्यायालय के साथ-साथ दूरस्थ बिन्दु पर भी समन्वयक के कार्य करेंगे।

5.3 दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक इनमें से कोई भी हो सकता है निम्नलिखित:

उप-नियम	जहाँ अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति निम्नलिखित बिंदु पर है:-	दूरस्थ दूरस्थ बिंदु समन्वयक होंगे:-
5.3.1	विदेशों में	भारतीय वाणिज्य दूतावास/संबंधित भारतीय दूतावास/भारत के संबंधित उच्चायोग का अधिकारी

***

5.3.11 खंड 5.3.1 के प्रावधानों के बावजूद, जहाँ देश के बाहर स्थित किसी व्यक्ति की आपराधिक मामले में गवाह से पूछताछ करनी है, "विदेश में जांच के लिए व्यापक दिशानिर्देश और अनुरोध पत्र जारी करना (एल.आर.)/पारस्परिक कानूनी सहायता (एम.एल.ए.) आपराधिक मामलों के संबंध में अनुरोध और समन/नोटिस/न्यायिक दस्तावेजों की तामील के प्रावधान"
(http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/ISII_ComprehensiveGuidelinesMutualLegal Assistance 17122019.pdf पर उपलब्ध है) का द.प्र.सं. और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पालन किया जाएगा। इसके अलावा, इससे पहले कि अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गवाहों से पूछताछ करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करे, वह आरोपी की सहमति प्राप्त करेगी..."

14. इस प्रकार, यह ध्यान दिया जा सकता है कि नियम 5.3.11 में प्रावधान है कि यदि न्यायालय वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किसी गवाह के साक्ष्य की

रिकॉर्डिंग की अनुमति देता है, जो विदेश में यानी भारत से बाहर है, तो ऐसे मामलों में आरोपी की सहमति प्राप्त की जाएगी।

15. उपरोक्त के संबंध में, यह न्यायालय नोट किया कि इसी तरह का तर्क विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया और उस पर दिनांक 09.12.2023 के आक्षेपित आदेश में निपटान किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा यह प्रेक्षित किया गया था कि अभियुक्तों की ओर से निहित सहमति थी, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री को पेश होने के लिए निर्देश दिया, और अभियुक्तों द्वारा 29.11.2023 तक आवेदन दायर करने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

16. अभिलेख पर रखे गए विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश पत्रों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि दिनांक 04.07.2022 के आदेश में, विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित डी.सी.पी. को "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री से पूछताछ करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया था, यदि वह शारीरिक रूप से अदालत में आने की स्थिति में नहीं है"। यह आदेश तीनों अभियुक्तों और अभियुक्त विनोद कुमार के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। इसके बाद, 11.07.2022 को, विद्वान विचारण न्यायालय ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से अभियोक्त्री को नए समन जारी किए थे और यह देखते हुए कि अभियोक्त्री

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है, न्यायालय ने इस बारे में विस्तृत निर्देश पारित किए थे कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्ता की ऐसी गवाही कैसे दर्ज की जाएगी। यह आदेश सभी अभियुक्तों और आरोपी विनोद कुमार के अधिवक्ता की उपस्थिति में भी पारित किया गया। इस आदेश में जारी किए गए निर्देशों को संदर्भ के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "1. गृह मंत्रालय को तदनुसार निर्देश दिया जाता है कि वह अमेरिका के लिए भारतीय दूतावास द्वारा भारत के महाकांसुलावास को अनुरोध पत्र जारी करे ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उनकी सरकार का समन्वय किया जा सके और नियमों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था के लिए इस निर्देश को अग्रेषित किया जा सके।
>
> 2. गवाही अदालत के घंटों के दौरान अर्थात पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे के बीच दर्ज की जाएगी।
>
> 3. वाणिज्य दूतावास अपनी तरफ से दुभाषिया की व्यवस्था भी करेगा।
>
> 4. भारत के अदालत के घंटों के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कर्मचारियों को रोकने के लिए महावाणिज्य दूतावास आवश्यक व्यवस्था करेगा।
>
> 5. संबंधित डी.सी.पी. को निर्देश दिया जाता है कि वह गृह मंत्रालय को दूरस्थ स्थान के आई.पी. विवरण सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का पूरा विवरण प्रदान करें और सभी आवश्यक जानकारी के साथ न्यायालय के आई.पी. विवरण को भी ब्योरेवार साझा करेंगे।
>
> I) संबंधित डी.सी.पी. को निर्देश दिया जाता है कि साक्ष्य के दौरान एन.आई.सी.एन.ई.टी. प्रणाली सुविधा की आवश्यक मंजूरी भी एन.आई.सी. के पक्ष में लें ताकि दूरवर्ती यानी दूरस्थ स्थान से पटियाला हाउस कॉम्प्लेक्स के वीडियो-कांफ्रेंसिंग सिस्टम के बीच कनेक्शन किया जा सके।

II) संबंधित डी.सी.पी. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दोनों स्थानों पर समन्वयक किसी भी तकनीकी समस्या को हल करने के लिए दोनों स्थानों के बीच सुनवाई की तिथि से दो दिन पहले एक परीक्षण करेंगे ताकि गवाही बिना किसी रुकावट के दर्ज की जा सके।

III) संबंधित डी.सी.पी. यह सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति से पूछताछ या सुनवाई की जानी है वह निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निर्धारित कमरे में उपलब्ध हो।

IV) संबंधित डी.सी.पी. को अमेरिका में भारतीय दूतावास के साथ समन्वय करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में नियंत्रित प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

V) प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंस पटियाला हाउस नई दिल्ली को संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए।

चूँकि जैसा कि अति.लो.अभि. द्वारा बताया गया है गवाही की रिकॉर्डिंग के दौरान, दस्तावेजों को भी गवाह के सामने रखा जाना आवश्यक है, इसलिए, डी.सी.पी. यह सुनिश्चित करेगा कि गवाहों को रखे जाने वाले दस्तावेजों का एक पूरा सेट उचित पृष्ठांकन के साथ अग्रिम रूप से तैयार की जाए और उसी का एक सेट ई-मेल के द्वारा गवाह को भेजा जाए और सुनवाई की तिथि से काफी पहले पोस्ट की जाए। अहलमद/आई.ओ. को इन दस्तावेजों का एक सेट तैयार करने और महावाणिज्य दूतावास को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

वीडियो द्वारा अभियोक्त्री की गवाही अदालत के घंटों के दौरान 27.10.2022, 28.10.2022 और 29.10.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक दर्ज की जाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त के अलावा, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 325/नियम/डीएचसी दिनांक 01.06.2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का पालन किया जाए।"

17. पुनः 20.04.2023 को, अभियोक्त्री की गवाही दर्ज करने के लिए इसी तरह के विस्तृत निर्देश पारित किए गए, जबकि अभियोक्त्री को नए समन जारी

किए गए। पिछले आदेशों की तरह, यह आदेश भी अभियुक्तों और अभियुक्त सं. 2 के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया था। इसी तरह, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के निर्देश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 11.09.2023 को पुनः जारी किया गया, जब अभियोक्त्री वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अदालत के समक्ष पेश हुआ था। अभियुक्त और उनके अधिवक्ता भी इस दिन विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे।

18. इसलिए, ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, विद्वान विचारण न्यायलय ने यह प्रेक्षित करते हुए कोई त्रुटि नहीं की कि अभियुक्तों के अधिवक्तागण ने अदालत द्वारा अभियोक्त्री को शारीरिक रूप से या आभासी रूप से पेश होने और यहां तक कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाही देने के लिए समन जारी करने पर कभी आपत्ति नहीं की थी, जिसके लिए समय-समय पर विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे।

19. हालाँकि, ऐसा प्रेक्षित करने के बाद, यह न्यायालय अन्यथा भी "न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021" के नियम 18 पर ध्यान देता है, जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

> "18. छुट देने की शक्ति
>
> उच्च न्यायालय यदि संतुष्ट हो जाता है कि किसी नियम के क्रियान्वन से अनुचित कठिनाई हो रही है, तो आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो न्यायोचित और

> न्यायसंगत तरीके से मामले का निपटान करने के लिए निर्धारित की जा सकती हैं, को समाप्त कर सकता है या शिथिल कर सकता है।"

20. नियम 18, इस प्रकार, इस न्यायालय को किसी विशिष्ट नियम की आवश्यकताओं को शिथिल करने या समाप्त करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है, जब यह स्पष्ट हो कि इस तरह के नियम के सख्त प्रयोग करने से अनुचित कठिनाई होगी, या अन्याय हो सकता है या इसमें शामिल पक्षकारों पर अनुचित बोझ उत्पन्न कर सकता है। नियम 18 को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य, जैसा कि प्रतीत होता है, नियमों के कठोर अनुप्रयोग के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणामों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।

21. इस प्रकार, इसके बाद होने वाली चर्चा में, यह न्यायालय इस बात की जांच करेगा क्या तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, अभियोक्त्री को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है, हालाँकि अभियुक्तों ने इसका विरोध किया है।

<u>क्या अभियोक्त्री को दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाही देने की अनुमति देने से अभियुक्त के निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन होगा?</u>

22. अभियुक्तों/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बार-बार जोर देकर कहा है कि कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अभियोक्त्री की गवाही की

वर्चुअल रिकॉर्डिंग की अनुमति देना दंड विधि और न्याय प्रणाली के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

23. यह न्यायालय, हालाँकि इस बात से सहमत है कि खुली अदालत की विचारण कार्यवाही के सिद्धांत की अवधारणा और अभियुक्त, बचाव पक्ष के अधिवक्ता और न्यायाधीश की उपस्थिति में खुली अदालत में मौखिक रूप से गवाही देने वाले गवाह से अधिक मौलिक कुछ भी नहीं होती है, हालाँकि, भारत में, यौन उत्पीड़न के गवाहों सहित कमजोर गवाहों के मामलों में एक अपवाद बनाया गया है।

24. वर्तमान याचिका के उचित न्यायनिर्णयन के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि पहले महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर किया जाए कि "कमजोर गवाह" कौन है और ऐसे गवाहों की गवाही कैसे दर्ज की जानी है।

क. कमजोर गवाहों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक मिसालें और निर्देश: इसकी शुरूआत कैसे हुई

25. 'कमजोर गवाहों' के विचार पर बहस की शुरुआत वर्ष 1996 से हुई, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह*** *(1996) 2 एस.सी.सी. 384* के मामले में बलात्कार के मामलों का विचारण बंद कमरे में करने पर जोर दिया था, जैसा कि दं.प्र.सं. की धारा 327 द्वारा परिकल्पित है। संदर्भ के लिए प्रासंगिक टिप्पणियों को यहां उद्धृत किया गया है:

"24. ये दोनों प्रावधान खुले विचारण के सामान्य नियम के अपवाद की प्रकृति में हैं। संशोधन के बावजूद, हालांकि, यह देखा गया है कि विचारण न्यायालय या तो संशोधन के प्रति सचेत नहीं हैं या इसके महत्व को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि शायद ही किसी के सामने ऐसा मामला आया है जहाँ अदालत द्वारा बंद कमरे में बलात्कार के मामले की पूछताछ और विचारण की गई हो। दं.प्र.सं. की धारा 327 की उप-धारा (2) में होने वाली अभिव्यक्ति कि बलात्कार की जांच और विचारण "बंद कमरे में किया जाएगा" न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अदालत पर बलात्कार आदि मामलों की सुनवाई हमेशा "बंद कमरे में" करने का कर्तव्य डालता है। अदालतें विधायिका द्वारा व्यक्त आशय को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए बाध्य हैं और इसके आदेश की अनदेखी नहीं करती हैं और उन्हें दं.प्र.सं. की धारा 327(2) और (3) के प्रावधानों का सहारा लेना चाहिए और बलात्कार के मामलों की सुनवाई बंद कमरे में करनी चाहिए। यह अपराध से पीड़ित को थोड़ा सहज होने और बहुत परिचित परिवेश में अधिक आसानी से प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम करेगा। बंद कमरे में विचारण से न केवल अपराध की पीड़िता के आत्म-सम्मान को ध्यान में रखते हुए और विधायी आशय के अनुरूप होगा, बल्कि अभियोक्त्री के साक्ष्य की गुणवत्ता में भी सुधार होने की संभावना है क्योंकि वह इतनी झिझक या संकोच नहीं करेगी कि जितनी की वह खुली अदालत में जनता की नजर के सामने कर सकती है। उसके साक्ष्य की बेहतर गुणवत्ता अदालतों को सच्चाई तक पहुंचने और झूठ से सच को अलग करने में मदद करेगी। इसलिए उच्च न्यायालयों को सलाह दी जाती है कि वे दं.प्र.सं. की धारा 327 के संशोधित प्रावधानों की ओर विचारण न्यायालय का ध्यान आकर्षित करें और पीठासीन अधिकारियों को दं.प्र.सं. की धारा 327(2) के द्वारा परिकल्पित खुली अदालत के बजाय बंद कमरे में बलात्कार के मामलों की सुनवाई करने के लिए दबाव डालें। जब बंद कमरे में सुनवाई होती है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए दं.प्र.सं. की धारा 327(3) द्वारा परिकल्पित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना, मामले की कार्यवाही के संबंध में किसी भी बात को छापना या प्रकाशित करना वैध नहीं होगा। यह यौन अपराध की पीड़िता को आगे होने वाली किसी भी शर्मिंदगी से बचाएगा। जहाँ भी संभव हो, यह भी

> विचार करने योग्य होगा कि क्या यह अधिक वांछनीय नहीं होगा कि महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाए, जहाँ भी उपलब्ध हो, ताकि अभियोक्त्री अधिक सहजता से अपना बयान दे सके और ऐसे मामलों में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय कठोर तकनीकी की वेदी पर सच्चाई का बलिदान करने की अनुमति दिए बिना अदालतों को अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन करने में सहायता कर सके। अदालतों को, जहाँ तक संभव हो, यौन अपराध के पीड़ित को और शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने आदेशों में अभियोक्त्री के नाम का खुलासा करने से बचना चाहिए। अपराध के पीड़ित की गुमनामी को यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने अपील के तहत अपने आदेश में पीड़िता के नाम का बार-बार इस्तेमाल किया है, जबकि वह उसे सिर्फ अभियोक्त्री के रूप में संदर्भित कर सकता था। हमें इस पहलू पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है और उम्मीद है कि विचारण न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 327(2) और (3) के प्रावधानों का सख्ती से सहारा लेंगे। बंद कमरे में बलात्कार के मामलों का विचारण नियम होना चाहिए और ऐसे मामलों में खुला विचारण अपवाद-स्वरूप होना चाहिए।

26. ***साक्षी बनाम भारत संघ*** *(2004) 5 एस.सी.सी. 518* में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***गुरमीत सिंह*** *(पूर्वोक्त)* में जारी निर्देशों के अलावा और निर्देश जारी किए थे, और यह भी देखा था कि यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता का साक्ष्य वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी दर्ज किया जा सकता है, और यह कि आरोपी को देखने मात्र से पीड़ित या गवाहों के मन में अत्यधिक भय पैदा हो सकता है। इन टिप्पणियों को लाभप्रद रूप से निम्नानुसार संदर्भित किया जा सकता है:

> "31. अदालत के समक्ष पूरी जांच सच्चाई को उजागर करने के लिए है, यह नितांत आवश्यक है कि पीड़ित या गवाह बिना किसी शर्मिंदगी के स्वतंत्र

वातावरण में पूरी घटना के बारे में गवाही देने में सक्षम हों। दं.प्र.सं. की धारा 273 में केवल आरोपी की उपस्थिति में सबूत लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह धारा यह नहीं कहती है कि साक्ष्य इस तरह से दर्ज किए जाने चाहिए कि आरोपी को पीड़ित या गवाहों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई के मामले में इस न्यायालय के हाल ही के फैसले में दं.प्र.सं. की धारा 273 के संबंध में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति दी गई है। अपराधों को परिभाषित करने वाले मूल प्रावधानों और इसके लिए सजा का प्रावधान करने और ऐसे अपराधों के परीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले प्रक्रिया संबंधी अधिनियमन के बीच बहुत अधिक अंतर है। प्रक्रिया के नियम न्याय की दासी हैं और न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हैं, न कि उसमें बाधा डालने के लिए। इसलिए, अदालत को सच्चाई को उजागर करने और पक्षकारगण के साथ न्याय करने के लिए ऐसे प्रावधानों के अर्थों का विस्तार या विस्तार करने की अनुमति है।

32. अभियुक्त की दृष्टि मात्र से पीड़ित या गवाहों के मन में अत्यधिक भय का तत्व उत्पन्न कर सकती है या उन्हें सदमे की स्थिति में डाल सकती है। ऐसी स्थिति में वह घटना का पूरा विवरण देने में सक्षम नहीं हो सकता/सकती है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हो सकती है। इसलिए कोई परदा या कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जहाँ पीड़ित या गवाहों को अभियुक्त के शरीर या चेहरे को देखने का सदमा न सहना पड़े। अक्सर प्रतिपरीक्षा में रखे गए प्रश्न जानबूझकर बलात्कार और बाल शोषण के पीड़ितों को शर्मिंदा या भ्रमित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। उद्देश्य यह रहता है कि शर्म या शर्मिंदगी की भावना से, पीड़ित अभियुक्त द्वारा किए गए कुछ कृत्यों के बारे में बात नहीं कर सकता है या विवरण नहीं दे सकता है। इसलिए, यह बेहतर होगा कि अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न लिखित रूप में अदालत के पीठासीन अधिकारी को दिए जाएं, जो पीड़ित या गवाहों को ऐसी भाषा में रख सकता है जो शर्मनाक नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अन्य सुझाव पर शायद ही कोई आपत्ति हो सकती है कि जब भी किसी बच्चे या बलात्कार की पीड़िता को

गवाही देने की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त विराम दिए जाने चाहिए। दं.प्र.सं. की धारा 327 की उप-धारा (2) के प्रावधान को भा.दं.सं. की धारा 354 और 377 के तहत अपराधों की जांच या विचारण में भी लागू होने चाहिए।

33. *पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह* में, इस न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 327(2) और (3) के प्रावधानों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और निर्देश जारी किया कि उपरोक्त प्रावधानों के आदेश की अनदेखी नहीं की जाय और अभिनिर्धारित किया कि बलात्कार के मामलों की सुनवाई बंद कमरे में की जाय। यह भी बताया गया कि इस तरह के विचारण में बंद कमरे में करने से अपराध पीड़ित को थोड़ा सहज होने और अधिक आसानी से प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाएगा और इस प्रकार अभियोक्त्री के साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि वहां वह इतनी संकोच या शर्म नहीं करेगी कि जितनी वह खुली अदालत में जनता की नजर के सामने कर सकती है। आगे यह भी निर्देश दिया गया है कि जहाँ तक संभव हो, ऐसे मामलों का विचारण महिला न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए, जहाँ भी उपलब्ध हो, ताकि अभियोक्त्री अधिक आसानी से बयान दे सके और कठोर तकनीकी की वेदी पर सच्चाई की बलि चढ़ाए बिना अदालत को अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निर्वहन करने में सहायता कर सके।

34. तदनुसार रिट याचिका का निपटान निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

(1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) के प्रावधान, उपधारा में उल्लिखित अपराधों के अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 377 के अधीन अपराधों की जांच या विचारण में भी लागू होंगे।
(2) बाल यौन शोषण या बलात्कार का विचारण के अभिनिर्धारण करने में:

(i) एक पर्दा या ऐसी कुछ व्यवस्था की जा सकती है जहाँ पीड़ित या गवाह (जो पीड़ित के सामान ही कमजोर हो सकते हैं) अभियुक्त के शरीर या चेहरे को न देखें;

(ii) अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जहाँ तक वे घटना से सीधे संबंधित हैं, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दिए जाने चाहिए जो उन्हें पीड़ित या गवाहों के समक्ष ऐसी भाषा में रख सकता है जो स्पष्ट है और लज्जाजनक नहीं है;

(iii) बाल शोषण अथवा बलात्कार पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय में गवाही देते समय जब कभी अपेक्षित हो, पर्याप्त विराम दिए जाने चाहिए।

ये निर्देश *पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह* में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त हैं।

35. याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे और समाज के व्यापक हित में हैं। बाल दुर्व्यवहार और बलात्कार के मामले खतरनाक गति से बढ़ रहे हैं और इसलिए इस संबंध में उपयुक्त कानून की तत्काल आवश्यकता है। हमें उम्मीद और विश्वास है कि संसद याचिकाकर्ता द्वारा उजागर किए गए बिंदुओं पर गंभीरता से ध्यान देगी और पूरी तत्परता के साथ उचित कानून बनाएगी, जिसकी वह हकदार है।

27. आगे बढ़ते हुए, वर्ष 2018 में, ***महाराष्ट्र राज्य बनाम बंडू उर्फ़ दौलत*** *(2018) 11 एस.सी.सी. 163* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कमजोर गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए दिल्ली में स्थापित विशेष केंद्रों पर ध्यान दिया था और आपराधिक मामलों में "कमजोर गवाहों से पूछताछ करने के लिए विशेष केंद्र" स्थापित करने के निर्देश जारी किए थे ताकि कमजोर गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। इस निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

"10. इस आदेश से अलग होने से पहले हम विद्वान न्यायमित्र के सुझाव पर विचार कर सकते हैं कि अदालत में अनुकूल माहौल के हित में आपराधिक मामलों में कमजोर गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष केंद्र होने

चाहिए ताकि कमजोर पीड़ित को बयान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे केंद्रों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान आपराधिक मामलों में कमजोर गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की ओर आकर्षित किया गया है और इस तथ्य की ओर भी कि इस उद्देश्य के लिए दिल्ली में चार विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं।

11. हमें उपरोक्त सुझाव में गुणागुण मिलती है। *साक्षी बनाम भारत संघ*, में इस न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे पर उचित विचार करने के बाद, निम्नलिखित निर्देश जारी किए: (एस.सी.सी. पृ. 545, पैरा 34)

***

12. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश और ऊपर उल्लिखित कमजोर गवाहों के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना इस न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं और उसी के पूरक हैं। हमारा विचार है कि सभी उच्च न्यायालय ऐसे दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं यदि उन्हें अभी तक ऐसे संशोधनों के साथ नहीं अपनाया गया है जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है। कमजोर गवाहों के लिए केंद्र की स्थापना शायद देश के लगभग हर जिले में आवश्यक हो सकती है। सभी उच्च न्यायालय इस दिशा में चरणबद्ध तरीके से उचित कदम उठा सकते हैं। आज से तीन महीने के भीतर प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कम से कम दो ऐसे केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। तत्पश्चात्, उच्च न्यायालयों के निर्णय के अनुसार ऐसे और केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे। इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भेजी जाए।"

28. हाल ही में, कमजोर गवाहों के साक्ष्य को दर्ज करने की योजना में एक ऐतिहासिक प्रगति हुई है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य*** *2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 78* के

मामले में 'कमजोर गवाह' शब्द के दायरे का विस्तार करते हुए निम्नलिखित निर्देश और दिशानिर्देश जारी किए हैं:

> 3. विचारण की कार्यवाही की निष्पक्षता के साथ-साथ वास्तविक न्याय की खोज उस महत्वपूर्ण तरीके द्वारा निर्धारित होती है जिसके द्वारा कमजोर गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। व्यक्ति की गरिमा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक आंतरिक तत्व है, को असंवेदनशील कार्यवाहियों की अनिश्चितता और शत्रुतापूर्ण वातावरण पर नहीं छोड़ा जा सकता है। न्याय तक पहुँच अनिवार्य करती है कि एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। ये वे बाधाएं हैं जो न केवल पारंपरिक अदालतों के वास्तविक स्थानों के भीतर मौजूद हैं, बल्कि वे कमजोर गवाहों के दिमाग और व्यक्तित्व पर भी काम करती हैं। एक बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के अंतर्निहित हितकारी उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने की तत्काल आवश्यकता है जहाँ शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की सीमाओं के बिना बयानों को स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जा सके। इसके लिए न केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है बल्कि सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता है।
>
> 4. इस न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया, जिसके अनुसरण में वे अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर, न्याय मित्र सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने 25 अक्टूबर 2021 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति का एक सारणीबद्ध विवरण तैयार किया। सारणीबद्ध विवरण की एक प्रति इस आदेश के उपाबंध “ए” में व्यापक संकेतक के रूप में संलग्न है। न्यायालय में कार्यवाही के दौरान हुए विवेचना, न्याय मित्र द्वारा प्रस्तावित सुझावों और उच्च न्यायालयों की ओर से उपस्थित हुए कुछ अधिवक्तागण की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, इस न्यायालय के पहले के निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य उन निर्देशों के

कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है जो 24 अक्टूबर 2017 को *बंडू (पूर्वोक्त)* और इससे पहले अन्य निर्णयों में दिए गए थे।

5. दिशानिर्देश नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

(i) **दिल्ली उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों में कमजोर गवाहों के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए दिशानिर्देश के खंड 3(क) में निहित "कमजोर गवाह" की परिभाषा केवल उन बाल गवाहों तक सीमित नहीं होगी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और अन्य बातों के साथ-साथ, कमजोर गवाहों की निम्नलिखित श्रेणियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए:**

(क) **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 273 और 327 तथा दंड संहिता, 1860 की धारा 354 सहपठित यौन उत्पीड़न के आयु तटस्थ पीड़ित;**

(ख) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(घ) सहपठित यौन उत्पीड़न के लिंग तटस्थ पीड़ित;

(ग) साक्षी (पूर्वोक्त) के निर्णय के पैराग्राफ 34 (1) सहपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 377 के तहत यौन उत्पीड़न के लिंग तटस्थ पीड़ित और आयु;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 सहपठित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 2(ध) के तहत परिभाषित "मानसिक बीमारी" से पीड़ित गवाह;

(ङ) किसी भी गवाह को केंद्र सरकार की गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत खतरे की आशंका माना जाता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा महेंद्र चावला बनाम भारत संघ मामले में अनुमोदित किया गया है;

(च) कोई भी बोलने या सुनने में अक्षम व्यक्ति या किसी अन्य विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा कमजोर गवाह माना जाता है; और

(छ) संबंधित न्यायालय द्वारा कमजोर समझा गया कोई अन्य गवाह।

(ii) उच्च न्यायालय इस आदेश की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कमजोर गवाह बयान केंद्र योजना को अपनाएंगे और अधिसूचित करेंगे जब तक कि कोई योजना पहले से ही अधिसूचित न हो। वे उच्च न्यायालय जिनके पास पहले से ही मौजूदा वी.डब्ल्यू.डी.सी. योजनाएं हैं, वे वर्तमान आदेश में इंगित दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं। **वी.डब्ल्यू.डी.सी. योजना तैयार करने में, उच्च न्यायालयों को उस योजना का उचित सम्मान करना होगा जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है,** जिसे बंडू (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के फैसले में विधिवत अनुमोदित किया गया है;

(iii) प्रत्येक उच्च न्यायालय को वर्तमान निदेशों के कार्यान्वयन का निरंतर पर्यवेक्षण करने और कमजोर गवाहों के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए अपेक्षित समय के अनुपात में प्रत्येक जिले में अपेक्षित वी.डब्ल्यू.डी.सी. की संख्या का आवधिक मूल्यांकन करने और आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन का समन्वय करने के लिए एक आंतरिक स्थायी वी.डब्ल्यू.डी.सी. समिति का गठन करना चाहिए;

(iv) प्रत्येक उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह प्रत्येक जिला न्यायालय (या अतिरिक्त सत्र न्यायालय) में कम से कम एक स्थायी वी.डब्ल्यू.डी.सी. स्थापित करने के लिए अपेक्षित जनशक्ति और अवसंरचना के लागत का आकलन करे और तीन महीने की अवधि के भीतर पूरे राज्य के लिए अपेक्षित वी.डब्ल्यू.डी.सी. की इष्टतम संख्या का अनुमान लगाएं;

(v) वी.डब्ल्यू.डी.सी. में कार्मिक आवश्यकता और उनका प्रबंधन करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा न्यायिक अधिकारियों, बार के सदस्यों और न्यायालय के कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हैं। समिति वी.डब्ल्यू.डी.सी. के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर उच्च न्यायालयों के साथ जुड़ने के अलावा एक अखिल भारतीय वी.डब्ल्यू.डी.सी. प्रशिक्षण

कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करेगी। अध्यक्ष का प्रारंभिक कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। सभी उच्च न्यायालय या संबंधित कार्य सौंपे गए को मॉड्यूल के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में सुविधा प्रदान करेंगे और पूर्ण सहयोग देंगे जो अध्यक्ष द्वारा तैयार किया जा सकता है;

(vi) प्रत्येक उच्च न्यायालय की वी.डब्ल्यू.डी.सी. समिति द्वारा तैयार की गई लागतों के प्राक्कलन पर, राज्य सरकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर या वित्तीय वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, अपेक्षित निधियों को शीघ्रता से मंजूरी देगी और परियोजना योजना के अनुसार उच्च न्यायालय को निधियों का संवितरण करेगी। राज्य सरकार वित्त विभाग के एक नोडल अधिकारी को नामित करेगी जो इन निर्देशों के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए उच्च न्यायालय की वी.डब्ल्यू.डी.सी. समिति के काम से पदेन रूप से जुड़ा होगा;

(vii) उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि चार महीने की अवधि के भीतर प्रत्येक जिला न्यायालय (या अतिरिक्त सत्र न्यायालय) में कम से कम एक स्थायी वी.डब्ल्यू.डी.सी. स्थापित की जाए। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे;

(viii) अनेक राज्यों में, उच्च न्यायालयों द्वारा जिलों में न्यायालयों के समीप ही ए.डी.आर. केन्द्रों की स्थापना की गई है। जहाँ ऐसे ए.डी.आर. केंद्र मौजूद हैं, उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता होगी कि वी.डब्ल्यू.डी.सी. ए.डी.आर. केंद्र के परिसर के भीतर उपलब्ध कराया जाए ताकि कमजोर गवाहों के बयानों को दर्ज करने के लिए एक सुरक्षित, अनुकूल और बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके;

(ix) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का, विशेष रूप से संवेदीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित करने में, महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और भूमिका है। इस न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि वे एन.ए.एल.एस.ए.

और एस.एल.एस.ए. के साथ जुड़ें (एन.ए.एल.एस.ए. के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा जारी किए जा सकने वाले निर्देशों के तहत) ताकि प्रशिक्षण के लिए योजना को लागू करने के लिए एक प्रभावी इंटरफेस प्रदान किया जा सके;

(x) उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, वर्तमान निदेशों को आगे बढ़ाने के लिए या तो प्रशासनिक पक्ष की ओर से या न्यायिक पक्ष की ओर से सभी समुचित उपाय करने और आवधिक आधार पर अनुपालन का निगरानी करने के लिए स्वतंत्र होंगे;

(xi) दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध है कि वे वी.डी.डब्ल्यू.सी. समिति प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय और अपेक्षित कर्मचारियों के लिए एक कार्य स्थान/कक्ष उपलब्ध कराएं, अधिमानतः ऐसे कार्मिक जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रशिक्षण मॉड्यूलों के विकास और कार्यान्वयन में सहायता की है और अध्यक्ष के परामर्श से कार्यक्रम के समन्वयक को नियुक्त करें। उचित लिपिकीय और संभारतंत्रीय सहायक कर्मचारी और उपकरण अध्यक्ष द्वारा निर्धारित उचित पारिश्रमिक पर समिति को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अध्यक्ष को देय मानदेय सहित इस संबंध में खर्च का भुगतान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक को किया जाएगा। अध्यक्ष इस आदेश की शर्तों के तहत उसे सौंपे गए कार्य के लिए उचित मानदेय तय कर सकता है। उस स्थिति में कि कोई और निर्देश आवश्यक हैं, अध्यक्ष उन्हें इस न्यायालय के समक्ष मांग सकता है और उस संबंध में कोई भी सूचना आगे के निर्देशों के लिए रखा जाएगा; और

(xii) केंद्र सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन निदेशों के कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा इस न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की अध्यक्ष, न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल को सभी प्रकार की संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। इसमें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अध्यक्ष को मानदेय का भुगतान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कार्यक्षेत्र (डोमेन) विशेषज्ञों को नियुक्त

करने सहित खर्चों को पूरा करना शामिल होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राज्यों में महिला और बाल विकास के सभी मंत्रालय अध्यक्ष के साथ समन्वय करेंगे और संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करेंगे। उच्च न्यायालय, समिति के अध्यक्ष के परामर्श से, सभी हितधारकों के उचित प्रशिक्षण और विकास की सुविधा के लिए क्षेत्र में विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करेंगे..."

ख. असुरक्षित गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखन: दिल्ली उच्च न्यायालय की योजना

29. यह न्यायालय, ***विरेन्द्र बनाम दिल्ली राज्य (रा.रे.क्षे.)*** *2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल. 4413* के मामले में कई दिशानिर्देश जारी किए थे, न्यायालयों में एक अलग कमरा हो जहाँ से बाल गवाह गवाही दे सकता है और बाल गवाह/पीड़ित बच्चे के आघात को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का अथवा क्लोज सर्किट टेलीविजन माध्यम का उपयोग करना शामिल है।

30. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, ***"अदालतों में कमजोर गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए दिशानिर्देश"*** इस न्यायालय द्वारा अभिकल्पित किए गए थे, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

31. इस न्यायालय द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों के अनुसार, "कमजोर गवाह" को एक ऐसे बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। हालांकि, इस योजना के प्रावधानों की जांच करते समय,

माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***स्मृति तुकाराम बडाडे*** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय के पैरा 5 (i) में, "कमजोर गवाह" शब्द के दायरे का विस्तार किया है, जिस पर पहले ही पिछली विवेचन में ध्यान दिया जा चुका है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक वयस्क महिला, जो बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के अपराध की पीड़ित है, को भी अब "कमजोर गवाह" की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

32. हालांकि यह न्यायालय योजना की पेचीदगियों में गहराई से जाने का इरादा नहीं रखता है, फिर भी साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से कमजोर गवाह का कक्षों के द्वारा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका संक्षिप्त अवलोकन करना उपयोगी होगा। संदर्भ के लिए कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को यहां उद्धृत किया गया है:

> "**3 (ठ) लाइव लिंक** - "लाइव लिंक" का अर्थ है और इसमें एक लाइव टेलीविजन लिंक, ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधन या अन्य व्यवस्था शामिल है, जिसके तहत एक गवाह, अदालत से अनुपस्थित रहते हुए भी साक्ष्य देने और प्रतिपरीक्षा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरस्थ संचार द्वारा अदालत में मौजूद होता है।
>
> ***
>
> **24. आरामदायक वातावरण प्रदान करने का कर्तव्य**
>
> अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह निर्देश जारी करके और पक्षकारगण, उनके अधिवक्ता, बाल गवाहों, सहायक व्यक्तियों, वादार्थ संरक्षक, मददकर्ता और अदालत कर्मियों सहित अदालत में सभी व्यक्तियों के लिए स्थान, आवाजाही और मंच व्यवहार की निगरानी करके कमजोर गवाह के लिए आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करे। बच्चे को गवाह की कुर्सी के अलावा

किसी अन्य स्थान से गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है। गवाह की कुर्सी या अन्य स्थान जहां से बच्चा गवाही देता है, उसकी गवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए घुमाया जा सकता है, लेकिन विरोधी पक्षकार और उसके अधिवक्ता के पास भी बच्चे की गवाही के दौरान वीडियो लिंक द्वारा बच्चे का ललाट या अर्द्ध मुख दिखाई पड़नी चाहिए। गवाह की कुर्सी या अन्य जगह जहां से बच्चा गवाही देता है, उसे भी बच्चे को विरोधी पक्षकार और उसके अधिवक्ता को देखने की अनुमति देने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, यदि वह उन्हें देखना चाहता है, तो उसके शरीर को मोड़े या गवाह कठघरा छोड़े बिना। ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने का निर्णय लेते समय, न्यायाधीश को अपने न्यायिक वस्त्र पहनने से छूट दी जा सकती है।

***

27. बाल पीड़ितों और गवाहों की गोपनीयता और भलाई की रक्षा के उपाय।

(1) पीड़ित बच्चे या गवाह के अनुरोध पर, उसके माता-पिता या अभिभावक, उसके अधिवक्ता, सहायक व्यक्ति, सहायता प्रदान करने के लिए नामित अन्य उपयुक्त व्यक्ति, या अदालत अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, कमजोर गवाह बच्चे की गोपनीयता और शारीरिक और मानसिक कल्याण की रक्षा करने और अनुचित संकट और अतिरिक्त उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक का आदेश दे सकती है:

***

(ङ) गवाही देने वाले बच्चे के लक्षणों या शारीरिक विवरण को छिपाने या गवाही देने सहित बच्चे को संकट या नुकसान से बचाने के प्रयास:

(i) परदे के पीछे;

(ii) छवि या आवाज बदलने वाले उपकरणों का उपयोग करना;

(iii) किसी अन्य स्थान पर पूछताछ करना, साथ ही साथ वीडियो लिंक के द्वारा अदालत में प्रेषित करना;

(iv) एक योग्य और उपयुक्त मध्यस्थ के द्वारा, जैसे कि, लेकिन सुनने, देखने, बोलने या अन्य विकलांग बच्चों के लिए दुभाषिया तक सीमित नहीं है;

(च) बंद सत्र आयोजित करना;

***

30. आपराधिक मामलों में लाइव-लिंक टेलीविजन गवाही जहां कमजोर गवाह शामिल है -

(क) अभियोजक, अधिवक्ता या वादार्थ संरक्षक इस आदेश के लिए आवेदन कर सकता है कि बच्चे की गवाही अदालत के बाहर एक कमरे में ली जाए और लाइव-लिंक टेलीविजन द्वारा अदालत कक्ष में प्रसारित की जाए।

(ख) लाइव-लिंक के उपयोग का निर्णय लेने के लिए न्यायाधीश कक्ष में, या अदालत के अलावा किसी अन्य आरामदायक जगह पर, सहायक व्यक्ति, वादार्थ संरक्षक, अभियोजक और पक्षकारों के अधिवक्ता की उपस्थिति में बच्चे से पूछताछ कर सकता है। न्यायाधीश के प्रश्न विचारण के मुद्दों से संबंधित नहीं होंगे, बल्कि अदालत में गवाही देने के बारे में बच्चे की भावनाओं से संबंधित होंगे।

(ग) न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, यदि उचित समझता है, तो एक कमजोर गवाह के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए (क) के अनुसार या किसी अन्य उपयुक्त निर्देश के संदर्भ में आदेश पारित कर सकता है।

ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की न्यायिक मिसालें

33. इस बिंदु पर, यह न्यायालय इस बात का विश्लेषण करना उचित समझता है कि क्या वैधानिक कानून और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक नजीर यौन उत्पीड़न की पीड़िता जो एक विदेशी नागरिक है, आपराधिक विचारण में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देती है।

34. इस संबंध में कानूनी ढांचे की जांच से पता चलता है कि इस मुद्दे पर ***महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई*** *2003 4 एस.सी.सी. 601* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यापक प्रतिपादना निम्नानुसार थे:

क) वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग दं.प्र.सं. की धारा 273 के उद्देश्य को संतुष्ट करती है, कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए, और अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।

ख) वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग में, पीड़ित और आरोपी दोनों एक-दूसरे की उपस्थिति में होते हैं, और स्पर्श करने के अलावा, कोई भी देख, सुन और निरीक्षण कर सकता है जैसे कि पक्षकार एक ही कमरे में है।

ग) जब गवाह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाही देता है तो गवाह का आचरण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

घ) चूंकि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण अदालत में स्थापित किए जा सकते हैं, इसलिए न्यायाधीश स्वयं या खुले न्यायालय में बोलकर लिखाने के द्वारा साक्ष्य रिकॉर्ड कर सकते हैं।

ङ) यदि उपकरण अदालत में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, तो दं.प्र.सं. की धारा 284 से 289 के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है, और गवाहों से पूछताछ के लिए अधिकार-पत्र जारी किया जा सकता है।

35. ***35. डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में निर्णय के प्रासंगिक अंश, जिसमें एक गवाह के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए जारी दिशानिर्देश शामिल हैं, जो अमेरिका का निवासी था, निम्नानुसार है:

> '... 19. इस स्तर पर हमें श्री सुंदरम द्वारा किए गए प्रस्तुति द्वारा निपटान करना चाहिए। **यह प्रस्तुत किया गया था कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अभियुक्त के अधिकारों को आभासी वास्तविकता से जुड़ी प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जा सकता है**। ऐसा तर्क आभासी वास्तविकता की अवधारणा और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। आभासी वास्तविकता एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को वह महसूस कराया जाता है, सुनाया जाता है या कल्पना की जाती है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। आभासी वास्तविकता में, किसी को ठंड का एहसास कराया जा सकता है जबकि वह गर्म कमरे में बैठा होता है, किसी को समुद्र की आवाज़ सुनाई दे सकती है जबकि वह पहाड़ों में बैठा होता है, तो किसी को यह कल्पना कराई जा सकती है कि वह ग्रांड प्रिक्स रेस भाग ले रहा है में जबकि वह एक सोफे पर आराम कर रहा होता है आदि। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का आभासी वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने अब दुनिया को छोटी कर दी है। वे अब दूर होने वाली घटनाओं को देखने और सुनने में सक्षम बनाते हैं, जैसे कि वे वास्तव में हो रही हैं।** उदाहरण के लिए आज विश्व कप के मैच देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी वह खेल अपने टीवी पर

देख सकता है, जैसा कि वह चल रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहा होता है, तो मैच उसकी दृष्टि/मौजूदगी में खेला जा रहा होता है और वह खिलाड़ियों की मौजूदगी में होता है। जब कोई व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर मैच देख रहा होता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह खिलाड़ियों की मौजूदगी में है बल्कि व्यापक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि मैच उसकी मौजूदगी में खेला जा रहा होता है। स्टेडियम में बैठा व्यक्ति और ड्राइंग रूम में बैठा व्यक्ति दोनों देख रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है जैसा कि हो रहा होता है। यह आभासी वास्तविकता नहीं है, यह यथार्थतः वास्तविकता है। कोई वास्तव में जो हो रहा है उसे देख और सुन रहा है। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक उन्नति है जो किसी को दूर किसी को देखने, सुनने और बात करने की अनुमति देता है, उसी सुविधा और आसानी के साथ जैसे कि वह आपके सामने यानी कि आपकी उपस्थिति में मौजूद है। वास्तव में वह एक परदे पर आपके सामने मौजूद रहता है। **स्पर्श करने के अलावा, कोई भी उसे देख सकता है, सुन सकता है और प्रेक्षित कर सकता है जैसे कि पक्षकार उसी कमरे में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों पक्षकार एक-दूसरे की मौजूदगी में होते हैं।** प्रत्यर्थी के अधिवक्ता की प्रस्तुति एक तर्क के समान हैं कि दूरबीन या दूरबीन के द्वारा देखने वाला व्यक्ति वास्तव में वह नहीं देख रहा होता है जो हो रहा होता है। यह प्रस्तुत करने के समान है कि दूरबीन या दूरबीन के द्वारा देखा गया व्यक्ति अवलोकन करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं है। **इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज किए जाने पर अभियुक्त और/या उसके अधिवक्ता मौजूद हैं, तब तक वह साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किया जा रहा है और इस प्रकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 273 की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। ऐसे साक्ष्य की रिकॉर्डिंग कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है।**

20. **वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग भी धारा 273 में प्रदत्त उद्देश्य को संतुष्ट करती है, कि साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में दर्ज किया जाए। अभियुक्त और उसका अभिवक्ता गवाह को स्पष्ट रूप से देख**

सकते हैं जैसे कि गवाह वास्तव में उनके सामने बैठा हो। वास्तव में, अभियुक्त गवाह को बेहतर तरीके से देखने में सक्षम हो सकता है, अगर वह भीड़ भरे अदालत कक्ष में कटघरे में बैठा होता। वे उसके आचरण का निरीक्षण कर सकते हैं। वास्तव में प्रतिश्रवण की सुविधा आचरण को बेहतर तरीके से अवलोकन करने में सक्षम करेगी। वे गवाह के बयान को सुन और फिर से सुन सकते हैं। अभियुक्त अपने अभिवक्ता को तुरंत निर्देश देने में सक्षम होगा और इस प्रकार गवाह की प्रतिपरीक्षा उतनी ही प्रभावी है, यदि बेहतर नहीं है। प्रतिश्रवण की सुविधा गवाह से प्रतिपरीक्षा करते समय एक अतिरिक्त लाभ देगी। गवाह का सामना दस्तावेजों या अन्य सामग्री या बयान से उसी तरह से किया जा सकता है जैसे कि वह अदालत में था। **वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य रिकॉर्ड किए जाने पर ये सभी उद्देश्य पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार अभियुक्त के प्रति कोई भी पक्षपात, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो, नहीं किया जाता है।** बेशक, जैसा कि इसके बाद निर्धारित किया गया है, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य रिकॉर्डिंग कुछ शर्तों पर होना चाहिए।

21. इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 274 और 275 पर भरोसा किया गया, जिसके लिए आवश्यक है कि साक्ष्य को मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं लिखित रूप में या खुली अदालत में उसके डिक्टेशन द्वारा लिया जाए। यह प्रस्तुत किया गया कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग वी.एस.एन.एल. के स्टूडियो में होनी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि यह अभियुक्त के मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके आदेश के तहत खुली अदालत में रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। **विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति ऐसी है कि अब अदालत में ही वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण स्थापित करना संभव है। उस स्थिति में साक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा या उसके डिक्टेशन द्वारा खुली अदालत में दर्ज किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो इन धाराओं की आवश्यकताएँ पूर्णतया पूरी होंगी।** हालांकि, इस पद्धति में एक खामी है। चूंकि गवाह अब अदालत में है, इसलिए कठिनाइयां हो सकती हैं यदि वह अदालत की अवमानना करता है या या झूठी गवाही देता है और यह तुरंत देखा जाता है कि उसने कि उसने झूठी गवाही दी है। इसलिए समझदारी के

तौर पर, खुली अदालत में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य केवल तभी होना चाहिए जब गवाह ऐसे देश में हो, जिसकी भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि है और जिसके कानूनों के तहत अदालत की अवमानना और झूठी गवाही भी दंडनीय है।

22. **हालांकि, भले ही उपकरण अदालत में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता में आदेश देने पर पर गवाहों से पूछताछ करने के प्रावधान हैं। धारा 284 से 289 आदेश देने पर पर गवाहों से पूछताछ से संबंधित है। हमारे उद्देश्यों के लिए धारा 284 और 285 प्रासंगिक हैं। वे निम्नानुसार हैं:**

***

इस प्रकार ऐसे मामलों में जहां न्याय के लिए गवाह आवश्यक है और ऐसे गवाह की उपस्थिति बिना किसी देरी, व्यय या असुविधा के प्राप्त नहीं की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों में ये अनुचित होगी, अदालत ऐसी उपस्थिति से छूट दे सकती है और गवाह से पूछताछ के लिए आदेश जारी कर सकती है। जैसा कि पहले ही इंगित किया गया था, डॉ. ग्रीनबर्ग ने साक्ष्य देने के लिए भारत आने से इनकार कर दिया है। न्याय के उद्देश्य के लिए उसकी गवाही जरूरी थी। भारत में अदालतें उसकी उपस्थिति प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अन्यथा भी, अमेरिका जैसे दूर-दराज के देश से गवाह की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए आम तौर पर देरी, व्यय और/या असुविधा होगी। ऐसे मामलों में साक्ष्य दर्ज करने के लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं। आम तौर पर ऐसी स्थिति में उस स्थान पर साक्ष्य दर्ज करना शामिल होता है जहां गवाह रहता है। हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने अब उस शहर/क़स्बा में वीडियो-कांफ्रेंसिंग के द्वारा ऐसे साक्ष्य दर्ज करना संभव बना दिया है जहां अदालत हैं। अतः ऐसे मामलों में जहां किसी गवाह की उपस्थिति देरी, खर्च या असुविधा के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, अदालत वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के लिए आदेश जारी करने पर विचार कर सकती है।

***

24. इस मामले में हमें इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। जहां तक इस मामले का संबंध है, यह प्रश्न कि क्या किसी ऐसे देश में साक्ष्य दर्ज करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है जहां कोई व्यवस्था नहीं है, अक्रियात्मक है। इस मामले में हम विचार कर रहे हैं कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं। सामान्यतः जब कोई आदेश जारी किया जाता है तो रिकॉर्डिंग उसी स्थान पर होनी चाहिए जहां गवाह रहता है। इस प्रकार धारा 285 में यह प्रावधान है कि आदेश को किसे निर्देशित किया जाना है। यदि गवाह भारत से बाहर है तो भारत और उस देश के बीच व्यवस्था की आवश्यकता होती है क्योंकि साक्ष्य दर्ज करने और उपस्थिति सुनिश्चित करने/बाध्य करने के लिए देश के किसी अधिकारी (अधिकतर न्यायिक अधिकारी) की सेवाओं की आवश्यकता होगी। हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नई प्रगति अदालत के अधिकारियों को उस शहर में, जहां वीडियो-कांफ्रेंसिंग सबूत दर्ज करने के होनी है, की अनुमति देती है। इस प्रकार, जहां गवाह साक्ष्य देने के लिए तैयार है, अदालत के अधिकारी को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आदेश पर साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। साक्ष्य स्टूडियो/हॉल में दर्ज किए जाएंगे जहां वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है। मुंबई की अदालत मुंबई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए आदेश जारी करेगी। इसलिए आदेश मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई को संबोधित किया जाएगा, जो वी.एस.एन.एल. के कार्यालय में जाने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी (अधिमानतः एक न्यायिक अधिकारी) को नियुक्त करेगा और प्रत्यर्थी की उपस्थिति में डॉ. ग्रीनबर्ग के साक्ष्य को रिकॉर्ड करेगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य दर्ज करते समय प्रत्यर्थी और उसके अधिवक्ता मौजूद हों और वे डॉ. ग्रीनबर्ग के आचरण का निरीक्षण करने और उनके बयान को सुनने में सक्षम हों। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्यर्थी के पास डॉ. ग्रीनबर्ग से प्रतिपरीक्षा करने का पूरा अवसर हो। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसी प्रक्रिया को अपनाना संभव नहीं यदि गवाह भारत से बाहर है और साक्ष्य देने का इच्छुक नहीं है।

25. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच समय का अंतर है। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रश्न यह उठता है कि कैसे और कौन डॉ. ग्रीनबर्ग को शपथ दिलाएगा। यह प्रस्तुत किया गया कि वीडियो छवि / ऑडियो रुकावटें / विकृतियां हो सकती हैं जो प्रसारण को अश्रव्य/अस्पष्ट बना सकती हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं होगा कि साक्ष्य दर्ज किए जाने के दौरान गवाह को प्रशिक्षित/सिखाया/प्रेरित नहीं किया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया गया कि अमेरिका में बैठा गवाह भारत के अदालत के किसी भी नियंत्रण के अधीन नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया गया कि गवाह दण्डमुक्ति के साथ झूठी गवाही दे सकता है और सजा के डर के बिना अदालत का अपमान भी कर सकता है क्योंकि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि गवाह उपस्थित नहीं हो सकता है और प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार भी कर सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि वाणिज्यिक स्टूडियो उपस्थित रहने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाते हैं और स्टूडियो में लाए जा सकने वाले कागजात की मात्रा को भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि गवाह से प्रतिपरीक्षा करने के उद्देश्य से उसे मूलग्रंथों और अन्य सामग्रियों को रखना मुश्किल होगा। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की लागत, यदि अनुमति दी जाती है, तो राज्य द्वारा वहन करनी होगी।

26. याद रखें कि जिस पर विचार किया जा रहा है वह आदेश पर साक्ष्य दर्ज करना है। आदेश पर साक्ष्य दर्ज करने के लिए समय निर्धारित करना हमेशा उस अधिकारी का कर्तव्य होता है जिसे साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इस प्रकार साक्ष्य को रिकॉर्ड करने वाले अधिकारी के पास वी.एस.एन.एल. के परामर्श से समय निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और जो यह जान पाएंगे कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे सुविधाजनक समय कौन सा है। प्रत्यर्थी और उसके अधिवक्ता को संबंधित अधिकारी के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुविधाजनक बनाना

होगा। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो मजिस्ट्रेट उपस्थिति को बाध्य करने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि जिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा, उसी को शपथ दिलाने का अधिकार होगा। वही अधिकारी शपथ दिलाएगा। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने वीडियो छवि / ऑडियो रुकावटों / विकृतियों के बारे में चिंता न करने के लिए पर्याप्त प्रगति की है। यहां तक कि अगर व्यवधान होते हैं तो वे अस्थायी अवधि के होंगे। निस्संदेह, एक अधिकारी को या तो भारत से या उस देश के वाणिज्य दूतावास/दूतावास से प्रतिनियुक्त करना होगा जहां साक्ष्य दर्ज किए जाने हैं, जो साक्ष्य दर्ज किए जाने के समय मौजूद रहेगा और जो यह सुनिश्चित करेगा कि साक्ष्य दर्ज किए जाने के दौरान उस कमरे में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जहां गवाह बैठा है। वह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि गवाह को प्रशिक्षित/सिखाया /प्रेरित न किया जाए। यह सलाह दी जाती है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है, कि गवाह को वाणिज्य दूतावास / दूतावास के कमरे में साक्ष्य देने के लिए कहा जाए। चूंकि साक्ष्य आदेश पर दर्ज किए जा रहे हैं, इसलिए साक्ष्य बाद में अदालत में पढ़े जाएंगे। इस प्रकार गवाह द्वारा अदालत का अपमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि साक्ष्य पढ़े जाने पर अदालत को पता चलता है कि गवाह ने झूठी गवाही दी है, तो आदेश पर किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, अदालत सबूतों की अनदेखी या अविश्वास कर सकती है। यह याद रखना चाहिए कि ऐसे मामले हुए हैं जहां आदेश पर साक्ष्य दर्ज किए गए हैं और जब तक इसे अदालत में पढ़ा गया, तब तक गवाह देश छोड़ चुका होता है। ऐसे भी मामले हुए हैं जहां विदेशी गवाह ने भारत की अदालत में गवाही दी और फिर विदेश चला गया। ऐसे सभी मामलों में अदालत झूठी गवाही देने पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी क्योंकि जब तक सबूतों पर विचार किया जाता और यह सुनिश्चित किया जाता कि झूठी गवाही दी गई थी, गवाह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया था। यहां तक कि उन मामलों में भी अदालत केवल सबूतों की अनदेखी या अविश्वास ही कर सकती है। प्रतिनियुक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्थी, उसके अधिवक्ता और एक सहायक को स्टूडियो में रहने अनुमति दी जाए जब सबूत दर्ज किए जा रहे हों। अधिकारी यह भी

सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्थी को स्टूडियो में वे कागजात/दस्तावेज लाने से न रोका जाए जिसकी उसे या उसके अधिवक्ता को जरूरत हो सकती है। हम इस प्रस्तुति में कोई दम नहीं देखते हैं कि प्रतिपरीक्षा में गवाह के सामने दस्तावेज या लिखित सामग्री रखना मुश्किल होगा। जिस पक्षकार के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, उसे कितनी भी मात्रा में लिखित सामग्री दिखाना अब संभव है। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक बार वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने के बाद, जहां तक संभव हो, इसे बिना किसी रूकावट के आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा, अगर यह पाया जाता है कि डॉ. ग्रीनबर्ग बिना किसी पर्याप्त कारण के निर्धारित समय(यों) पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट के पास वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं देना खुला होगा। यदि अधिकारी को पता चलता है कि डॉ. ग्रीनबर्ग प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो अधिकारी उसी का एक मेमो बनाएगा। अंत में, जब साक्ष्य को न्यायालय में पढ़ा जाता है, तो यह एक ऐसा पहलू है जिसे साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। निस्संदेह, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की लागत राज्य को वहन करनी होगी।

27. तदनुसार, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। मजिस्ट्रेट अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डॉ. ग्रीनबर्ग के साक्ष्य दर्ज कराने की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। चूंकि विचारण लंबे समय से लंबित है, इसलिए विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि वह आज से एक साल के भीतर मामले का जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में निपटान करे। इन निर्देशों के साथ अपीलों का निपटान किया जाता है। प्रत्यर्थी राज्य और शिकायतकर्ता को इन अपीलों की जुर्माने का भुगतान करेगा ..."

(जोर दिया गया)

36. इसी तरह, भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत अपराध से जुड़े एक मामले में, जहां शिकायतकर्ता आयरलैंड का नागरिक था और डबलिन का निवासी था, विचारण न्यायालय ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिकायतकर्ता की गवाही दर्ज करना स्वीकार किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***सुजॉय***

मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य *(2015) 16 एस.सी.सी. 615,* के मामले में यह निर्णय दिया कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिकायतकर्ता के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की अनुमति देते हुए, आगे निर्देश भी जारी किया था जिनका पालन किया जाना है, जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "3. हमने विरोधी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को बहुत विस्तार से सुना है, और संतुष्ट हैं, कि अभियोजक साक्ष्य 5 के बयान को रिकॉर्ड करते समय, आक्षेपित आदेश में प्रदान किए गए कदमों और सुरक्षा उपायों के अलावा, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए:
>
> 3.1. पश्चिम बंगाल राज्य मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए वीसी सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त उपकरण स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की सेवाएं लेकर विचारण न्यायालय में अभियोजक साक्ष्य 5 की गवाही दर्ज करने का प्रावधान करेगा। यह प्रावधान पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा संबंधित सत्र न्यायाधीश द्वारा पहचाने जाने वाले कमरे में आज से चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा। एन.आई.सी. यह सुनिश्चित करेगा कि विचारण न्यायालय के परिसर में स्थापित उपकरण, डबलिन में आयरलैंड में भारतीय दूतावास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं के अनुरूप है।
>
> 3.2. अभियोक्त्री का बयान दर्ज करने से पहले, अभियोजक साक्ष्य 5, दूतावास एक जिम्मेदार अधिकारी को नामित करेगा, जिसकी उपस्थिति में बयान दर्ज किया जाना है। उक्त अधिकारी उक्त गवाही की रिकॉर्डिंग के प्रत्येक सत्र की शुरुआत से अंत तक हर समय उपस्थित रहेगा।
>
> 3.3. बयान दर्ज करने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि संबंधित गवाह के अलावा उस कमरे में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, जिसमें अभियोजक साक्ष्य 5 की गवाही दर्ज की जानी है। यदि गवाह के पास कोई सामग्री या दस्तावेज हैं तो उसे संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में ले लिया जाएगा।

3.4. इसके बाद गवाह का बयान दर्ज किया जाएगा। गवाह को संबंधित अधिकारी की अभिरक्षा में सामग्री और दस्तावेजों पर भरोसा करने या केवल विचारण न्यायलय की स्पष्ट अनुमति से साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

3.5. संबंधित अधिकारी बयान दर्ज करने से पहले विचारण न्यायलय को इस तथ्य की पुष्टि करेगा कि उस कमरे में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था जहां सबूत दर्ज किया गया है, और इसके अलावा, अभियोक्त्री, अभियोजक साक्ष्य 5 (यदि कोई हो) के कब्जे में सभी सामग्री और दस्तावेज (यदि कोई हो), बयान दर्ज करने से पहले उसके द्वारा उसकी अभिरक्षा में ले लिए गए थे। वह गवाही की समाप्ति पर विचारण न्यायलय को आगे पुष्टि किया कि गवाह के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान, उसके अंत तक कोई अन्य व्यक्ति कमरे में प्रवेश नहीं किया था। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता विचारण न्यायालय की सहायता करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उपरोक्त प्रक्रिया को वर्तमान आदेश पर भरोसा करके अपनाया गया है।

3.6. गवाह का बयान विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 278 के प्रावधानों के अनुरूप दर्ज किया जाएगा। बयान दर्ज करने की समाप्ति पर, उसे अभियुक्त की उपस्थिति में (यदि उपस्थिति है, या उसके अधिवक्ता को) गवाह को पढ़ कर सुनाया जाएगा। यदि गवाह साक्ष्य के किसी भी भाग की सत्यता से इनकार करता है, जो उसे पढ़ कर सुनाया गया है, तो विचारण न्यायालय आवश्यक सुधार कर सकता है, या वैकल्पिक रूप से, गवाह द्वारा दर्ज बयान पर की गई आपत्ति के लिए उस पर एक ज्ञापन दर्ज कर सकता है, और इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो अपनी टिप्पणी रिकॉर्ड कर सकता है।

3.7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 278 के प्रावधानों के अनुरूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दर्ज गवाह के बयान की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो, तो सही किया गया), स्कैन किया जाएगा और दूतावास को ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा। दूतावास में, गवाह कानून के अनुरूप इसे प्रमाणित करेगा।

उपरोक्त प्रमाणित बयान का दूतावास द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा समर्थन किया जाएगा। इसे स्कैन किया जाएगा और ईमेल के द्वारा विचारण न्यायालय को वापस किया जाएगा। दूतावास में गवाह द्वारा हस्ताक्षरित बयान को सीलबंद लिफाफे में उसकी अभिरक्षा में रखा जाएगा।

3.8. विचारण न्यायालय को ईमेल द्वारा प्राप्त बयान को विचारण न्यायाधीश द्वारा पुनः अनुमोदित किया जाएगा। विचारण न्यायाधीश द्वारा समर्थित वर्तमान बयान, सभी आशयों और उद्देश्यों के लिए अभियोक्त्री, अभियोजक साक्ष्य 5 की गवाही होगी।

4. हम संतुष्ट हैं, कि उपरोक्त मानदंड न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेंगे, और आगे किसी इनपुट की आवश्यकता नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियोजक साक्ष्य 5 के बयान को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विरोधी पक्षकारगण के लिए विद्वान अधिवक्ता की अमूल्य सहायता से अंतिम रूप दिया गया।

***

7. तदनुसार वर्तमान अपील का निपटान किया जाता है। विचारण न्यायालय सुनवाई की तारीख तय करेगी, जब भी विचारण न्यायालय के परिसर में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की जाएगी, और उसके बाद डबलिन में आयरलैंड में भारतीय दूतावास में उपलब्ध सुविधाओं के साथ तालमेल किया गया।

घ. दांडिक विचारण में अभियुक्त और पीड़ित के अधिकारों को संतुलित करते हुए प्रौद्योगिकी को अपनाना

37. पूर्ववर्ती विवेचन के मद्देनजर, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि खुली अदालत में सुनवाई और गवाह की उपस्थिति के बारे में मौलिक कानून, न्यायिक मिसाल द्वारा संशोधित किया गया है, जैसे कि विवेचन की गई है,

और इसके परिणामस्वरूप कमजोर गवाह योजनाओं को अपनाया गया है, जिसका पूरे देश में पालन किया जा रहा है। यह न्यायालय भी यह नोट किया है कि ये योजनाएं व्यक्तिगत रूप से अपने साक्ष्य दर्ज करने के बजाय, प्रौद्योगिकी के द्वारा यौन उत्पीड़न के गवाहों सहित कमजोर गवाहों से पूछताछ के लिए एक विकल्प प्रदान करती है।

38. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज की दुनिया में तकनीक इतनी उन्नत है कि गवाह की गवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा दर्ज की जा सकती है और इसे आपराधिक कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों से समझौता किए बिना आसानी से पूरा किया जा सकता है।

39. यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति की गवाही दर्ज करने के लिए शारीरिक उपस्थिति के बदले वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर चर्चा किए गए मामलों में अनुमति दी गई है, और यह इस न्यायालय द्वारा जारी "अदालतों में कमजोर गवाहों के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार, कमजोर गवाहों से जुड़े मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं में से एक है।

40. विचारण के समय पीड़ित और अभियुक्त के शारीरिक आमने-सामने के टकराव के बजाय, कमजोर गवाहों द्वारा कमरे के उपयोग और ऐसी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उनकी गवाही दर्ज करने का इतिहास और उद्देश्य है।

41. इस न्यायालय का विचार है कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा जिसके द्वारा अभियोक्त्री की गवाही दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है, वर्तमान मामले में भी, **वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की एकतरफा सुविधा नहीं है, बल्कि दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा है,** जिसमें अभियुक्त, पीड़ित, विद्वान अभियोजक, विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता और विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है और आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी सिद्धांतों का पालन किया गया है, जैसे:

(क) गवाह के नियम का प्रबंधन करना;

(ख) विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, बचाव पक्ष के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक की उपस्थिति में गवाह की गवाही को दर्ज करना, वे सभी गवाह को देखने में सक्षम होंगे;

(ग) विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाह की प्रतिपरीक्षा।

ङ. वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य अर्थात गवाह के आचरण की रिकॉर्डिंग

42. इस याचिका में उठाई गई चिंताओं में से एक यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय गवाह की विश्वसनीयता का आकलन करने में सक्षम हो सकता है यदि गवाह/अभियोक्ता को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाही देने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि न्यायाधीश गवाह के आचरण का आकलन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जहां तक इस तर्क का सवाल है, इस अदालत की

राय है कि गवाह का शारीरिक आचरण गवाह की विश्वसनीयता का एकमात्र मानदंड या निर्धारक नहीं हो सकता है। हालांकि, साथ ही, गवाह का आचरण न्यायाधीश को तब भी दिखाई देगा जब वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज किया जा रहा हो, और उन मामलों में भी जहां गवाहों की गवाही कमजोर गवाह कक्षों में दर्ज की जाती है। गवाह परदा पर विद्वान विद्वान विचारण न्यायालय, विद्वान अभियोजक और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को भी दिखाई देगा।

43. यहां तक कि "न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021" भी व्यवहार को नोट करने के महत्व को ध्यान में रखते हैं, और नियम 8.6 में, निम्नानुसार प्रदान करता है:

> "8. व्यक्तियों से पूछताछ
>
> ***
>
> 8.6 न्यायालय को पूछताछ किए जा रहे व्यक्ति के आचरण को रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता होगी ..."

44. जैसा कि ***डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई*** *(पूर्वोक्त)* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया, ऐसे मामलों में जहां वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं, अभियुक्त गवाह को अदालत से बेहतर तरीके से देखने में सक्षम हो सकता है और आचरण का बेहतर अवलोकन भी संभव होगा।

45. इस न्यायालय की यह भी राय है कि गवाह के साक्ष्य का आकलन और समझने की विद्वान विचारण न्यायालय की क्षमता कानून और मामले के तथ्यों के अनुसार होगी, और यह वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री की गवाही के तथ्य से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी। यदि गवाह को एक बड़े आकार के परदे पर उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, तो विद्वान विचारण न्यायधीश, बचाव पक्ष के अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अभियोजक और अभियुक्त भी गवाह को देख पाएंगे, जब वह गवाही दे रही होगी और उससे प्रतिपरीक्षा की जाएगी। इसलिए, उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता, भरोसे की लायकता और गुणवत्ता की कसौटी गवाही यानी मुख्य पूछताछ और प्रतिपरीक्षा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा और अन्य कारकों पर निर्भर करेगी, जिन्हें आपराधिक मामले का फैसला करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

च. क्या 'विकसित देश से आने वाली शिक्षित महिला' को 'कमजोर गवाह' की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है?

46. इस मामले से अलग होने से पहले, यह न्यायालय नोट किया कि वर्तमान याचिका में उठाए गए आधारों में से एक, आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए, यह है कि चूंकि यहां अभियोक्त्री एक परिपक्व और शिक्षित महिला है, जो एक विकसित देश की है, इसलिए उसकी एक कमजोर बाल गवाह के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है।

47. इस तरह की अभिवचनों की सराहना करते हुए, "कमजोर" शब्द का अर्थ समझना प्रासंगिक होगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, "कमजोर" का अर्थ “आसानी से शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुँचाना, प्रभावित करना, या आघात करने में समर्थ होना है”। मरियम वेबस्टर "कमजोर" को *"शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुँचाने में सक्षम होने"* के रूप में परिभाषित किया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, "भेद्यता" शब्द का तात्पर्य *“लोगों, संसाधनों, संपत्ति, पर्यावरण के उस परिमाण से है जो नुकसान पहुंचाने, ख़राब होने, नष्ट होने या शत्रुतापूर्ण कारकों के संपर्क में आने के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं"।*

48. गौरतलब है कि यौन उत्पीड़न के मामले में, **गवाह की भेद्यता उसकी वित्तीय या शैक्षिक पृष्ठभूमि या उसके किसी विकसित या अविकसित देश से होने से संबंधित नहीं है, बल्कि भेद्यता उसके मानसिक और शारीरिक आघात के संबंध में है, जो उसे वातावरण और अभियुक्त की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील बनाती है, अभियुक्त की वास्तविक उपस्थिति से वह उसके द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के दर्दनाक अनुभव से गुजरेगी और फिर से उसे जीएगी।**

49. **यौन उत्पीड़न का प्रभाव सार्वभौमिक रूप से विनाशकारी है, लेकिन पीड़ित जो किसी अन्य देश में न्याय मांगने वाला विदेशी नागरिक है, उसे भावनात्मक आघात विशेष रूप से तीव्र हो सकता है। किसी विदेशी न्यायालय में दर्दनाक**

अनुभव को याद करने का कार्य एक परेशान करने वाली और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, और न्यायालयों को ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। इस प्रकार, न्याय की खोज में, न्यायालयों के लिए उन अनूठी परिस्थितियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जो यौन उत्पीड़न के पीड़ितों, जो विदेशी नागरिक हैं, के मामलों से जुड़ी हैं। ऐसे उदाहरणों में जहां एक महिला विदेशी धरती पर एक दर्दनाक घटना का अनुभव करती है, जैसे कि भारत में जैसा कि वर्तमान मामले में है, न्यायालय को संभावित पुन: आघात के बारे में पता होना चाहिए जो विचारण के उद्देश्य से उस विदेशी भूमि पर पीड़ित की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता के परिणामस्वरूप हो सकता है।

50. ऐसे मामलों का फैसला करते समय न्यायालयों को पीड़ित पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को ध्यान में रखना होगा, और पीड़ित को बार-बार उस देश में वापस जाने के लिए कहना जहां उत्पीड़न हुआ था, पीड़ित को इससे और अधिक भावनात्मक आघात लगने की संभावना है। अतः, न्यायालयों को संभावित पुन: उत्पीड़न को पहचानना चाहिए जो हर बार हो सकता है जब पीड़ित को उस देश का दौरा करने के लिए मजबूर किया जाता है जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। इसलिए, इस विवेचन के आलोक में, यह न्यायालय मानता है कि इस मामले में गवाह की भेद्यता उसके पुन: उत्पीड़न और पुन: आघात के संबंध में है, यदि उसे यात्रा करने और भारत

में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अभियुक्तों की उपस्थिति में गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है।

51. ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालयों के लिए वैकल्पिक तंत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है जो पीड़ित पर अनावश्यक बोझ डाले बिना निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित कर सकता है, जो एक विदेशी नागरिक है और इसलिए, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता के तर्क को खारिज किया जाता है।

<u>निष्कर्ष</u>

52. यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना है कि उसके समक्ष सभी पक्षकारगण को उचित व्यवहार और निष्पक्ष विचारण मिले, लेकिन साथ ही, उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसे कमजोर गवाहों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे विचलित न हों या अपने डर और आघात के पीछे न छिपें, जो न्याय के प्रभावी प्रशासन और कानून का शासन लागू करने को हतोत्साहित करेगा। निष्पक्षता की अवधारणा में हालांकि निस्संदेह आवश्यकता है कि अभियुक्त के अधिवक्ता को अपने मुवक्किल का प्रभावी ढंग से बचाव करने की स्थिति में होना चाहिए, हालांकि, दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और आज के तकनीकी युग में गवाह के गवाही की रिकॉर्डिंग को अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

53. इस मामले में पीड़ित एक महत्वपूर्ण गवाह है और दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा निष्पक्ष आपराधिक विचारण के सभी महत्वपूर्ण तत्वों को संरक्षित करने, दृढ़ रहने और उसका पालन करने में सक्षम है। गवाह की भेद्यता के मुद्दे को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि गवाह से प्रभावी ढंग से प्रतिपरीक्षा करना अभियुक्त का अधिकार था जो केवल अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थिति में ही संभव होगा।

54. उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, और इस न्यायालय द्वारा "न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम 2021", में प्रभावी रूप से और पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित की गवाही कानून के अनुसार दर्ज की गई है और प्रतिपरीक्षा का तरीका कठोर प्रतिकूल पूछताछ के तहत हुई है।

55. किसी अन्य देश में एक विदेशी नागरिक के यौन उत्पीड़न के मामले में गवाही देने का आघात, इस न्यायालय की राय में, आमने-सामने के टकराव के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के उपयोग को सही ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण कारक है। दोतरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से प्राप्त गवाही प्रतिकूल नहीं है और न ही यह प्रभावी प्रतिपरीक्षा के अभियुक्त के

अधिकार से इनकार करने के बराबर है। यह न्यायालय इस तथ्य पर भी जोर देता है कि दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और उसके द्वारा पीड़ित की गवाही दर्ज करने को अभी भी विश्वसनीयता के पारंपरिक मापदंडों के अधीन होना होगा और प्रतिपरीक्षा के आधार पर विश्वसनीयता की कसौटी पर परीक्षण किया जाएगा।

56. वर्तमान मामले में, यह पीड़ित या अभियुक्त की सुविधा मात्र नहीं है जो दो-तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीड़ित की गवाही को रिकॉर्ड करने की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए निर्णायक कारक है। इन अभिवचनों और निष्कर्ष का न्यायनिर्णयन और ऐसे आदेशों के तथ्य को पक्षकारगण की सुविधा से परे जाना होगा और प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक परिस्थिति पर निर्भर होना होगा। इसी तरह, इस आदेश का निष्कर्ष और इसके तथ्य, जिसके परिणामस्वरूप दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के द्वारा पीड़ित की गवाही दर्ज करने को सही ठहराया गया है, अतिरिक्त रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि यह उस सुविधा के समान होगा जो कि भारत में कमजोर गवाह कक्षों वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के उपयोग द्वारा किया जाता है।

57. इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि दो-तरफा वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभियोक्त्री के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने से याचिकाकर्ताओं के निष्पक्ष विचारण के अधिकार से से वंचित

करने के समान नहीं होगा, हालांकि इससे इनकार करना पीड़ित को न्याय तक पहुंच के उचित अधिकार से वंचित करने के बराबर हो सकता है।

58. इसलिए, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं दिखती है। हालांकि, विचारण न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि अभियोक्त्री का बयान दर्ज करते समय ***डॉ. प्रफुल्ल बी. देसाई*** *(पूर्वोक्त)* और ***सुजॉय मित्रा*** *(पूर्वोक्त)* के मामलों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

59. तदनुसार, लंबित आवेदन के साथ, वर्तमान याचिका का निपटान किया जाता है।

60. इस आदेश की प्रति निदेशक (अकादमिक), दिल्ली न्यायिक अकादमी को इसकी सामग्री पर ध्यान देने के लिए भेजी जाए। इसे दिल्ली के न्यायिक अधिकारियों को उनके संबंधित प्रधान, जिला और सत्र न्यायाधीशों के द्वारा भी परिचालित किया जाए।

61. निर्णय को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. स्वर्ण कांता शर्मा

22 दिसंबर, 2023/जेड.पी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*